मनीष अग्निहोत्री

दम तोड़ गईः देश के अन्य कुपोषित बच्चों की तरह (दाएं) शाहीना परवीन ने गत सप्ताह सरकारी सहायता की राह ताकते सांस छोड़ दी

खतरे की घंटी से

राज्य में बच्चों की स्थिति पर यूनिसेफ के सहयोग से तैयार रिपोर्ट से उम्मीद है कि नियोजन प्रक्रिया से दरकिनार इन बेबसों की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया जाएगा

■ फरज़ंद अहमद

वाराणसी की धन्नीपुर बस्ती में रहने वाली दुबली-पतली और बहुत ही कम वजन वाली शाहीना परवीन राज्य को देश की आर्थिक मुख्यधारा में ले जाने के उत्तर प्रदेश सरकार के सपने और हर बात में अड़ंगा लगाती संगदिल नौकरशाही के बीच खड़ी थी. गत सप्ताह सरकारी सहायता की बाट जोहते थक चुकी और दो साल की उम्र में महज तीन किलो वजन की इस बच्ची ने उसी दिन दम तोड़ा जब सरकार ने वह रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया था कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय में 4.03 प्रतिशत की वृद्धि से वह 10,224.38 रु. से बढ़कर 10,637.20 रु. हो गई.

धन्नीपुर के ज्यादातर निवासियों के लिए इसके कोई मायने नहीं हैं. उनके कुपोषित बच्चे जिंदगी-मौत के बीच संघर्ष जो कर रहे हैं. शाहीना की मौत के कुछ दिन पूर्व उसका दो वर्षीय पड़ोसी शहाबुद्दीन चल बसा था. उसका वजन छह किलो भी नहीं था. और इसी आयु वर्ग के कम वजन वाले 12 और बच्चे हैं, जो पीड़ादायक अंत की प्रतीक्षा कर रहे हैं. उनकी उपेक्षा किए जाने की वजह भी है: वे उन बुनकरों के बच्चे हैं, जिनके करघे कभी चमचमाती सिल्क साड़ियां बुनते थे. आज उनके मां-बाप उनके लिए भोजन और दवाई का इंतजाम कर पाने में असमर्थ हैं. शाहीना को ही लें. वह ईंटों से बने एक अंधेरे, गुफानुमा कमरे में रहती थी. उसकी मां ज़ाहिरा ने हाशिए पर जी रहे परिवारों के लिए काम कर रही संस्था पीपुल्स विजिलेंस कमेटी फॉर ह्यूमन राइट्स (पीवीसीएचआर) के स्वयंसेवकों से कहा था, ''भोजन? कुछ दिन तो हमें दोपहर का खाना नसीब होता है और कुछ दिन रात का. मुझे याद नहीं, दोनों वक्त का खाना हमने कब खाया था.'' मोक्षदायिनी शिवनगरी की बाहरी सीमा पर स्थित एक गांव में पीवीसीएचआर के डॉ. लेनिन रघुवंशी को तब झटका लगा जब गांववासियों ने उनकी टीम को बताया था कि स्थानीय प्रशासन ने उनकी मदद करने के बजाए उन्हें 'गरीबी रेखा से ऊपर' के कार्ड वितरित किए हैं, जिससे वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली का राशन पाने के पात्र नहीं रहे. उनका कहना है, ''मई में ही कुपोषण के शिकार बच्चों के मां-बाप ने जिलाधिकारी से मिलकर तत्काल सहायता का अनुरोध किया था, पर किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी.''

शहाबुद्दीन की मौत और अन्य बच्चों की करुण

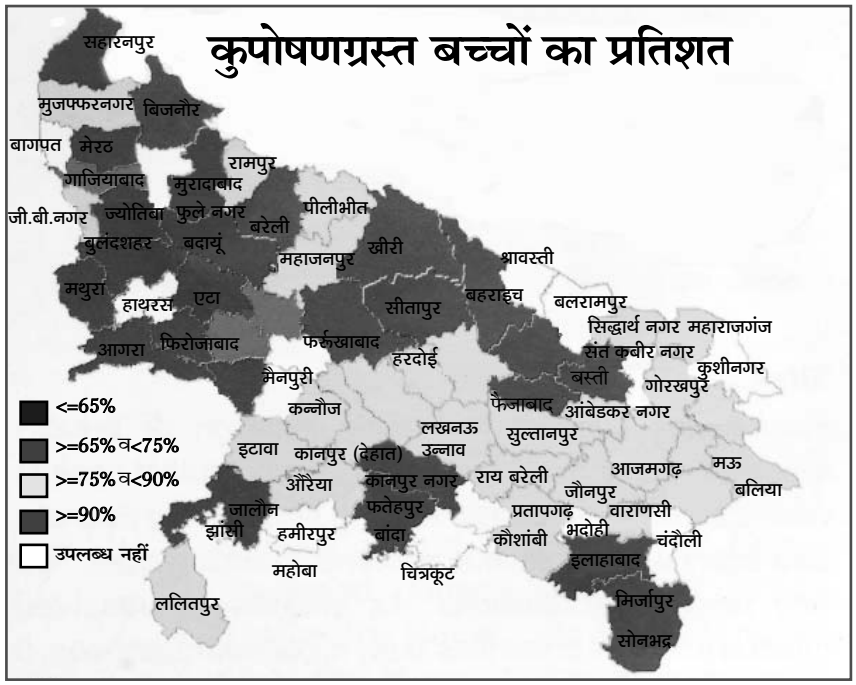

मनीष अग्निहोत्री

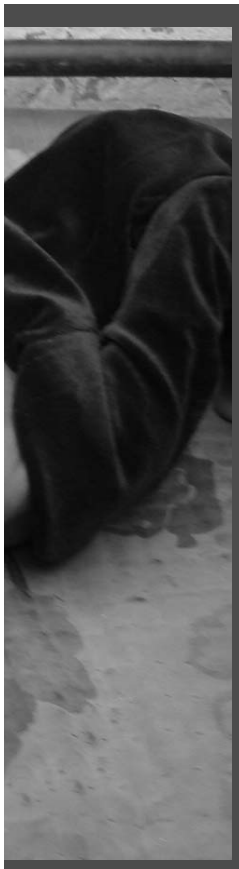

जाग उठी सरकार

गाथा पर राज्य सचिवालय में किसी ने उफ तक नहीं की, पर इससे दुनिया हिल गई. हांगकांग स्थित एशियन ह्यूमन राइट्स कमीशन (एएचआरसी) के बिजो फ्रांसिस ने विश्व भर में एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें कहा गया था, ''शहाबुद्दीन की जब मौत हुई तो उसका वजन छह किलो था. यह तृतीय श्रेणी का कुपोषण है, जो सोमालिया सरीखे देशों में ही सुना गया है. पर उत्तर प्रदेश में सोमालिया जैसी निकम्मी सरकार नहीं है. यहां निर्वाचित सरकार है. इसके मंत्री और सचिव शासन के नाम पर महंगे, वातानुकूलित वाहनों में राज्य भर की यात्रा करते हैं. यहां गद्दी पर एक महिला मुख्यमंत्री है, जिसने राज्य से भेदभाव और गरीबी का खात्मा करने की शपथ ली है.''

बात सही है. महीना भर पहले वाराणसी के डिवीजनल कमिश्नर बनकर आए सुरेशचंद्र ने माना कि प्रशासन को बच्चों की मदद करने की चिंता है. उन्होंने जिलाधिकारी से गांव का दौरा करने को कहा, जिन्होंने अधिकारियों का एक दल वहां भेजा और अब प्रखंड विकास अधिकारी और उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी रोज बच्चों की स्थिति पर नजर रखते हैं. धन्नीपुर के बच्चे उत्तर प्रदेश में कुपोषण का शिकार बच्चों की बढ़ती संख्या का ही हिस्सा हैं. इससे सरकार सचमुच चिंतित है और अधिकारियों के अनुसार, उसे पहली बार एहसास हुआ कि जाति और वर्ग की सीमाएं तोड़कर बच्चों में व्यापक और जबरदस्त कुपोषण उत्तर प्रदेश की

बच्चों में कुपोषण को लेकर सरकार सचमुच चिंतित लगी और अधिकारियों के अनुसार, उसे पहली बार एहसास हुआ कि जाति और वर्ग की सीमाएं तोड़कर यह समस्या प्रदेश की अवनति का एक कारण है.

क्या कहती है रिपोर्ट

- देश में 43 प्रतिशत बच्चे बेहद कुपोषित हैं, प्रदेश में यह आंकड़ा 52 प्रतिशत है.
- राज्य में पैदा होने वाले हर तीसरे शिशु का वजन कम होता है, यानी 1,200 ग्राम से कम है.
- राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के अपहरण के मामलों में उत्तर प्रदेश का हिस्सा 23 प्रतिशत है.
- राज्य में बच्चों की हत्याएं देश में होने वाली ऐसी हत्याओं का 39.2 प्रतिशत हैं.
- देश में जापानी इंसेफेलाइटिस के कुल मामलों में से 60 प्रतिशत उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं.

अवनति का एक कारण है. लखनऊ स्थित गिरी इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज के साथ जुड़े जाने-माने अर्थशास्त्री प्रो. डी.एम. दिवाकर ने भी चेतावनी दी थी कि कुपोषण बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर उलटा असर डालता है. इसका समूचे राष्ट्र और राज्य के मानवीय संसाधनों और आर्थिक विकास पर गहरा असर होता है. इससे पहले यूनिसेफ ने भी खतरे की घंटी बजाई थी कि यदि सरकार नहीं जागी तो विकास का उसका सपना दुस्वप्न बनकर रह जाएगा.

सरकार जागी और राज्य के योजना विभाग के प्रमुख सचिव वी. वेंकटाचलम ने बच्चों के अध्ययन के लिए यूनिसेफ के साथ नाता जोड़ा. हाल ही में वेंकटाचलम ने पहली बार वह संयुक्त रिपोर्ट जारी की, जिसका शीर्षक था 'उत्तर प्रदेश में बच्चों की स्थिति'. इसे पढ़कर रौंगटे खड़े हो जाते हैं. इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में 52 प्रतिशत बेहद कुपोषित बच्चे हैं, तो देश भर में 43 प्रतिशत हैं. इसमें यह भी बताया गया है कि सबसे कम विकसित जगत के बच्चों में कुपोषण का प्रतिशत मात्र 35 है तो दक्षिण एशिया में यह 42 प्रतिशत है और विकासशील देशों में 26 प्रतिशत ही है.

वेंकटाचलम का कहना था कि देश में अपनी तरह की यह पहली रिपोर्ट राज्य को अपना ध्यान फिलहाल नियोजन प्रक्रिया से दरकिनार बच्चों पर केंद्रित करने के लिए समर्थ बनाएगी और 11वीं योजना के दौरान उनकी विशेष समस्याओं को हल करने में सहायक होगी. इससे पता चलता है कि कुपोषण किस कदर बच्चों की जीवन स्थितियों को प्रभावित करता है. ''विडंबना है कि बच्चों की कुल मौतों में से आधी कुपोषण की वजह से होती हैं और भारत के 7.20 करोड़ कुपोषित बच्चों में से एक करोड़ से अधिक उत्तर प्रदेश में हैं.'' मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और बुंदेलखंड क्षेत्र में ज्यादातर जिलों में कुपोषण के बहुत मामले हैं. इसके अलावा, राज्य में शिशु और मातृ मृत्यु दर—प्रति 1,000 पर 73—बहुत ज्यादा है. देश में हर साल मरने वाले 25 लाख बच्चों में से करीब 4 लाख

क्या कहते हैं विशेषज्ञ

''यदि सरकार और समाज कुपोषण की एक-चौथाई समस्या को भी हल कर लें तो उत्तर प्रदेश और अंततः भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद में 1-2 प्रतिशत वृद्धि कर सकता है.''

उत्कर्ष सिन्हा,
निदेशक, समकालीन अध्ययन एवं शोध केंद्र, लखनऊ

''कुपोषण बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर उलटा असर डालता है. इसका समूचे राष्ट्र और राज्य के मानवीय संसाधनों और आर्थिक विकास पर गहरा असर होता है.''

प्रो. डी.एम. दिवाकर,
अर्थशास्त्री, गिरि इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज, लखनऊ

''*उत्तर प्रदेश में बच्चों की स्थिति* को लेकर अपनी तरह की यह पहली रिपोर्ट राज्य को अपना ध्यान फिलहाल नियोजन प्रक्रिया से दरकिनार बच्चों पर केंद्रित करने के लिए समर्थ बनाएगी और 11वीं योजना के दौरान उनकी विशेष समस्याओं को हल करने में सहायक होगी.''

वी. वेंकटाचलम,
प्रमुख सचिव, योजना विभाग, उ.प्र. सरकार

उत्तर प्रदेश के हैं और राज्य में पैदा होने वाले हर तीसरे बच्चे का वजन 1,200 ग्राम से कम होता है.

किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष डॉ. एम.ज़ेड. इदरीस के अनुसार, ''कुपोषण से बच्चे का समूचा विकास रुक जाता है, जिसकी वजह से राज्य अथवा देश के आर्थिक विकास पर असर पड़ता है. इससे मस्तिष्क का विकास प्रभावित होता है. नतीजा यह होता है कि मानसिक और शारीरिक शक्ति प्रभावित होती है.''

रिपोर्ट के अनुसार, पीने योग्य पानी और कम सफाई की स्थिति चिंताजनक है. पर चिंता का यह अकेला कारण नहीं है. नवजात से लेकर छह साल तक के बच्चों में कुपोषण के अलावा उनके साथ दुर्व्यवहार और उनसे संबंधित अपराध के सबसे अधिक मामलों, खासकर पूर्वांचल में व्यापक और अनियंत्रित जापानी इंसेफेलाइटिस और सर्वाधिक बाल श्रम ने—जो घोर निर्धनता की उपज हैं—देश के सबसे बड़े राज्य को कमजोर बच्चों का प्रदेश बना दिया है. समकालीन अध्ययन एवं शोध केंद्र के निदेशक उत्कर्ष सिन्हा के मुताबिक, अर्थशास्त्रियों, योजनाकारों और विशेषज्ञों ने पाया है कि यदि सरकार और समाज कुपोषण की एक-चौथाई समस्या को भी हल कर लें तो उत्तर प्रदेश और अंततः भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद में 1-2 प्रतिशत वृद्धि कर सकता है.''

पर यह परिदृश्य पहली बार राज्य को आर्थिक विकास के मोर्चे पर फैली अव्यवस्था की वजहें समझाने में सहायक रहा. चार करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन के बावजूद राज्य की 17 करोड़ आबादी में से 30 प्रतिशत से ज्यादा लोगों को बमुश्किल एक वक्त का खाना नसीब होता है और उसमें भी पोषक तत्व शायद ही होते हैं. योजना आयोग की 'उत्तर प्रदेश विकास रिपोर्ट' के मुताबिक, यह राज्य भले ही देश में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक होने का दावा करे, इसकी प्रति व्यक्ति पैदावार अन्य राज्यों के मुकाबले बहुत कम है. इसके अलावा, रिपोर्ट के अनुसार, आर्थिक सुधारों के बाद के दौर में अविभाजित उत्तर प्रदेश में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की औसत सालाना वृद्धि अखिल भारतीय स्तर के 6.3 प्रतिशत के मुकाबले 4.22 प्रतिशत थी. 2001-02 से लेकर 2002-03 के हाल ही के दौर में औसत सालाना वृद्धि मात्र करीब 2.24 प्रतिशत रही है. इसी तरह

संजय सोनकर

घोर निर्धनता के शिकार: लखनऊ की सड़कों पर भीख मांगता एक बच्चा

मनीष अग्निहोत्री

सबसे बड़ी चुनौतीः गोरखपुर के अस्पताल में जापानी इंसेफेलाइटिस के शिकार बच्चे

प्रति व्यक्ति आय भी राष्ट्रीय आंकड़े के मुकाबले 47 प्रतिशत ही थी (यानी 21,373 रु. की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के मुकाबले राज्य का यह आंकड़ा 11,856 रु. था). दुखद तो यह है कि 1980-81 में यह फर्क मात्र 17.2 प्रतिशत था, जो 2002-03 में करीब 47.7 प्रतिशत हो गया.

बेहद कमजोर पीढ़ी से भरपूर राज्य में इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं की जा सकती थी. लेकिन समग्र बाल विकास सेवा के निदेशक चंद्र प्रकाश राज्य की ऐसी शोचनीय स्थिति की वजहें गिनाते हैं. ''बहुत ज्यादा आबादी और शिक्षा का अभाव समेत इसके कई सामाजिक कारण हैं. दिलचस्प है कि राज्य कुपोषित बच्चों की देखभाल पर सालाना 600-700 रु. खर्च कर रहा है. इसके अलावा, प्राइमरी स्कूल स्तर पर करीब 40 प्रतिशत बच्चे चूंकि बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं इसलिए उन्हें सरकार और स्वयंसेवी एजेंसियों का मुहैया कराया जा रहा दुपहरी भोजन नहीं मिलता.''

उत्तर प्रदेश कुपोषित ही नहीं, बीमार भी है. बच्चों को मौत के कगार पर धकेलने वाली अन्य बीमारियों के अलावा जापानी इंसेफेलाइटिस हर साल बच्चों को हड़प जाने वाला सबसे बड़ा दानव सिद्ध हुई है. रिपोर्ट में स्वीकार किया गया है, ''जापानी इंसेफेलाइटिस राज्य में बहुत बड़ी चुनौती है. देश में जापानी इंसेफेलाइटिस के कुल मामलों में से 60 प्रतिशत उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं.'' रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में जापानी इंसेफेलाइटिस से होने वाली मौतों की संख्या लगातार बढ़ी है. 1994 में यह 35 थी तो 2005 में 228 हो गई. पूर्वांचल में तो यह मौत की प्रमुख वाहक है. पर रिपोर्ट में व्यक्त सरकारी चिंता के मुकाबले नौकरशाही ने इस पर नियंत्रण के लिए कुछ खास नहीं किया. जापानी इंसेफेलाइटिस के मामलों के अलावा प्रशासन की ओर से इसके लिए मुहैया कराई गई राहत पर नजर रखने वाली गोरखपुर स्थित निगरानी संस्था एक्शन फॉर पीस, प्रॉसपेरिटी ऐंड लिबर्टी (एपीपीएल) ने पिछले हफ्ते कहा कि इस रोग के औसतन 10 नए मामले हर माह गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में लाए जाते हैं, जहां इस साल जनवरी के बाद से 300 से अधिक बच्चे इलाज करवा रहे हैं और 74 की मृत्यु हो चुकी है. यही नहीं, प्रशासन ने बेहद बीमार बच्चों के इलाज में भी रोड़े अटकाए. एपीपीएल के एक संस्थापक डॉ. संजय श्रीवास्तव ने बताया कि राज्य सरकार ने जब मेडिकल कॉलेज के जापानी इंसेफेलाइटिस वार्ड से जुड़े सभी विशेषज्ञों का तबादला करने का फैसला किया तो कॉलेज प्रशासन तथा डाक्टरों को झटका लगा. हालांकि अदालत ने आदेश दिया था कि रिटायर होने वाले इंसेफेलाइटिस विशेषज्ञों को बरकरार रखा जाए और रोग नियंत्रण कार्यक्रम से जुड़े डॉक्टरों का तबादला नहीं किया जाए.

ताकतवर नौकरशाह और कैबिनेट सचिव शशांक शेखर सिंह उम्मीद करते हैं कि *उत्तर प्रदेश में बच्चों की स्थिति* को लेकर रिपोर्ट बच्चों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों को सुलझाने की दिशा में एक नई शुरुआत है.

लेकिन रिपोर्ट के इस रहस्योद्घाटन से दुनिया को झटका लगा कि राज्य के ज्यादातर बच्चे अपराध का शिकार हैं. इसके मुताबिक, राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के अपहरण के मामलों में उत्तर प्रदेश का हिस्सा 23 प्रतिशत है. राज्य में बच्चों की हत्याएं देश में होने वाली ऐसी हत्याओं का 39.2 प्रतिशत हैं. 2004 के दौरान देश में बच्चियों के साथ बलात्कार के जो 3,542 मामले बताए गए हैं, उनमें उत्तर प्रदेश बाकी राज्यों के साथ तीसरे क्रम पर है.

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की प्रकाशित हाल ही की एक रिपोर्ट से पता चला है कि 2003-04 के बीच देश में बच्चों के साथ हुए अपराध में 24 प्रतिशत की चिंताजनक वृद्धि हुई है. 2003 में ऐसे मामलों की संख्या 11,633 थी, जो 2004 में बढ़कर 14,423 हो गई. राज्यों में 1,921 मामलों के साथ उत्तर प्रदेश का क्रम तीसरा था. पर 2004 में 2,248 मामलों होने से इसमें 10.2 प्रतिशत की कमी आई. रिपोर्ट के अनुसार, अपहरण के 735 मामलों के साथ उत्तर प्रदेश इसमें प्रथम रहा.

लेकिन घोर अपराध तो बच्चों से बलात्कार का है—उत्तर प्रदेश में 2003 में इसके 394 मामले बताए गए, जो देश में बच्चों से होने वाले बलात्कार के कुल मामलों का 11.12 प्रतिशत है. 2004 में बच्चों से बलात्कार के मामले में उत्तर प्रदेश क्रम में तीसरा राज्य रहा. दूसरे अपराधों की तरह बलात्कार की घटनाएं भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा हुईं. ऐसी अधिक घटनाओं वाले 11 जिलों में सात इसी इलाके में स्थित हैं. गोरखपुर विवि में जाने-माने सामाजिक मनोविशेषज्ञ प्रो. अशोक कुमार सक्सेना का कहना है कि इस तरह की सामाजिक पाशविकता की कई वजहें हैं. इनमें रिश्तेदारों के साथ अंतरंग संबंध बनाने की इच्छा समेत कई सामाजिक प्रवृत्तियां हैं. समाज भी जिम्मेदार है क्योंकि लड़कियां अक्सर परिवार में अवांछनीय होती हैं. प्रो. सक्सेना कहते हैं, ''इन हालात में कन्या लघु वयस्क की तरह बढ़ती है और सच कहें तो तरुणाई की शुरुआत से पूर्व ही उसे हर चीज के अनुभव के लिए बाध्य किया जाता है.''

जाहिर है, दुनिया में सातवें बड़े देश जितना उत्तर प्रदेश कमजोर बच्चों का प्रदेश बन गया है. सरकार यह स्थिति बदलना चाहती है और राज्य में अभी तक हुए सबसे शक्तिशाली नौकरशाह, कैबिनेट सचिव शशांक शेखर सिंह उम्मीद करते हैं कि 'उत्तर प्रदेश में बच्चों की स्थिति' को लेकर रिपोर्ट ''बच्चों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों को सुलझाने की दिशा में एक नई शुरुआत है.'' ■